



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, १८ दिसम्बर, १९९५/२७ अग्रहायण, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-१७१००२, ३१ अक्तूबर, १९९५

संख्या एल० एल० आर०-ए०(३)-१/९५.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ (१९८७ का ३९) की धारा २८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, १९९५ है।

(२) ये नियम, उस तारीख जिसे राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे, से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है;
- (ख) “मुख्य न्यायमूर्ति” से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अभिप्रेत है;
- (ग) “अध्यक्ष” से राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष अभिप्रेत है, या यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष या यथास्थिति जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, या यथास्थिति, ताल्लुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, अभिप्रेत है;
- (घ) “जिला प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ङ) “उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति” से अधिनियम की धारा 8-अ के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, अभिप्रेत है;
- (च) “सचिव” से अधिनियम की धारा-6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव अभिप्रेत है, या, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 8-अ के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव अभिप्रेत है, या यथास्थिति, अधिनियम की धारा-9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है;
- (छ) “राज्य प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा-6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ज) “ताल्लुक विधिक सेवा समिति” से अधिनियम की धारा-11(अ) के अधीन गठित ताल्लुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है;
- (झ) “ताल्लुक” से जिले में उपमण्डल अभिप्रेत है;
- (ञ) इन नियमों में प्रयुक्त दूसरे सभी शब्दों और पदों के वे ही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनको समनुदेशित हैं।

3. राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं.— (1) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या मुख्य संरक्षण और कार्यकारी अध्यक्ष सहित पंद्रह से अधिक नहीं होगी।

(2) राज्य प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :—

- (i) राज्य के महाधिवक्ता;
- (ii) सचिव, वित्त विभाग;
- (iii) सचिव, विधि विभाग;
- (iv) हिमाचल प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष;
- (v) राज्य के पुलिस महानिदेशक;
- (vi) सचिव, कल्याण विभाग;
- (vii) राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नामनिर्दिष्ट जिला प्राधिकरण के दो अध्यक्ष।

(3) राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अन्य ऐसे सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकती है, जो इस नियम के उप नियम-4 में विहित अनुभव और अर्हताएं रखता हो।

(4) कोई भी व्यक्ति राज्य प्राधिकरण का सदस्य नामनिर्दिष्ट होने के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह :—

(क) कोई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि समाज के कमजोर वर्गों, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी हैं, के उत्थान में संलिप्त है, या

(ख) विधि या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति, या

(ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विशेषतया विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध हो।

4. राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य.—राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित होंगे :—

(क) पात्र और कमजोर वर्गों को निशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करना;

(ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विधिक सेवा स्कीमों और कार्यक्रमों की रूपात्मकता का परिकल्पना, और उनके दक्षतापूर्ण प्रबोधन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

(ग) राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक, गृह व्यवस्था, वित्त और बजट मामलों के विषय में शक्तियों का प्रयोग करना;

(घ) राज्य प्राधिकरण की सम्पत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबन्ध करना;

(ङ) राज्य प्राधिकरण के समुचित और सही लेखों का रखरखाव जिसमें उनकी समय-समय पर सामयिक लेखा परीक्षा और जांच भी सम्मिलित है;

(च) उक्त प्राधिकरण की वार्षिक आय और व्यय और तुलन पत्र का लेखा तैयार करना;

(छ) सामाजिक कार्य समूह और जिला और ताल्लुक विधिक सेवा प्राधिकारियों से सम्पर्क करना;

(ज) अद्यतन और पूर्ण सांख्यिक सूचना, जिसमें समय-समय पर विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति भी सम्मिलित है, का रख-रखाव;

(झ) वित्तीय सहायता के प्रस्तावों की प्रक्रिया और उनके उपयोग प्रमाण-पत्रों को जारी करना;

(ञ) राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन करना और, विधिक सेवा कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यशाला और सेमिनार/बैठकें बुलाना और उन पर रिपोर्ट तैयार करना और उस पर की गई कार्रवाई का अनुसरण करना;

(ट) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनसाधारण को सूचित करने के लिए विडियो/वृत्त चित्रों, प्रचार सामग्री और प्रकाशनों को बनाना;

(ठ) ग्रामीण विवादों के प्रस्तावों पर जोर डालना और ग्रामीण लोगों के लिए उनके द्वार पर ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिए प्रभावी और अर्थपूर्ण विधिक सेवा की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना;

(ड) ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो कि धारा-4(ख) के अधीन प्रतिपादित स्कीमों के अधीन उसे सौंपी गई हैं;

(ढ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कि राज्य प्राधिकरण के लिए दक्षतापूर्ण संचालन के लिए समीचीन हैं।

5. राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधि और अन्य शर्तें.—(1) राज्य सरकार द्वारा नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि 2 वर्ष होगी और वे पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र होंगे।

(2) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण का सदस्य राज्य सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से हटाया जा सकेगा, यदि—

(क) वह राज्य प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों में या 2 वर्ष की अवधि के भीतर हुई पांच बैठकों में बिना युक्तियुक्त कारण से उपस्थित होने में असफल रहता है; या

(ख) वह न्यायनिर्णीत दिवालिया हो, या

(ग) वह ऐसे अपराध में दोष सिद्ध ठहराया गया हो, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित हो; या

(घ) वह शारीरिक या मानसिक तौर पर सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो; या

(ङ) उसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो जिससे कि उसका राज्य प्राधिकरण में बने रहना लोक हित में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य प्राधिकरण का कोई भी सदस्य उस नियम की धारा (घ) में विनिर्दिष्ट आधार पर हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य सरकार द्वारा उसे इस निमित्त निर्देश दिए जाने पर, उस द्वारा ऐसी प्रक्रिया, जैसी कि वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, के अनुसार जांच करने पर, भिन्नता न करे कि सदस्य, ऐसे आधार पर, हटाया जाना चाहिए।

(4) सदस्य अपने हाथ से निखकर, अध्यक्ष को सम्बोधित करके, राज्य प्राधिकरण से त्यागपत्र देगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से राज्य सरकार, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इसे स्वीकृत करेगी, या त्यागपत्र देने की तारीख से 30 (तीस) दिन के अवसान के भीतर, जो भी पूर्वतम हो।

(5) यदि नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य, किसी भी कारण से राज्य प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहता है तो रिक्ति उसी रीति के अनुसार भरी जाएगी जिससे मूल नामनिर्दिष्ट हुआ है और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य को शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(6) उप नियम (7) के उपबन्धों के अध्वबन्ध, नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सभी सदस्य, राज्य प्राधिकरण के कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे और राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित वित्त विनियम विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सो)-बी (7)-2/88 तारीख 24-5-1995 में अन्तर्विष्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे।

(7) यदि नामनिर्दिष्ट सदस्य सरकारी कर्मचारी है, तो वह उन दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते लेने का हकदार होगा जिन पर वह, उसे लागू होने वाले सेवा नियमों के अधीन, हकदार है और वह उन्हें राज्य प्राधिकरण से न लेकर वह उन्हें उस विभाग से लेगा, जिसमें वह कार्यरत है।

(8) राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव, पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(9) सदस्य सचिव, सभी विषयों में जैसे, सेवा निवृत्ति की आयु, वेतन और भत्ते, लाभ और उपलब्धियां; और अनुशासनात्मक विषयों में, राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को यथा लागू नियमों द्वारा शासित होगा और वह राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होगा।

6. राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी.—राज्य प्राधिकरण अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए राज्य प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा पदों के सृजन के अध्वधीन, प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

7. मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के लिए विशेष उपबन्ध.—(1) उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश होने के कारण, मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण के कार्य के सम्बन्ध में, की गई यात्राओं के लिये यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के संदाय का हकदार होगा और राज्य प्राधिकरण द्वारा समय समय पर यथा संशोधित उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियम 1959 के उपबन्धों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे।

(2) राज्य प्राधिकरण द्वारा, राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, को, यदि वह उच्च न्यायालय का सेवा-निवृत्त न्यायाधीश हो तो, एक स्टाफ कार और चालक उपलब्ध करवाया जाएगा और चालक के वेतन और भत्ते तथा कार के रखरखाव और मरम्मत के कारण होने वाला व्यय उक्त प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।

8. कार्यकारी अध्यक्ष की सेवा शर्तें यदि वह सेवा निवृत्त न्यायाधीश है.—जहां कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है—

(i) उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी की भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय, खर्चा विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या: 19048/7/80-ई-IV, तारीख 8 अक्टूबर, 1987 या आयोगों/समितियों में नियुक्त उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लागू किए जाने वाले राज्य सरकार के ऐसे अन्य सुसंगत आदेशों में विनिर्दिष्ट है।

(ii) वह राज्य प्राधिकरण द्वारा संदत्त, 500 रुपये प्रति मास की दर से सत्कार भत्त का हकदार होगा।

(iii) उसे राज्य के अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

9. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन तथा भत्ते.—(1) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी सभी विषयों में, जैसे कि सेवा निवृत्ति की आयु, वेतन, भत्ते लाभ और उपलब्धियाँ और अनुशासनात्मक विषयों में ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे जैसे कि राज्य सरकार के समतुल्य पदधारक कर्मचारियों की लागू हैं।

(2) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और लाभों, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित की जाए, के हकदार होंगे।

10. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं:—जब तक कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार की पक्ति से नीचे के स्तर का उच्च न्यायालय का अधिकारी न हो तब तक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव की नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा।

11. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतन तथा भत्ते.—(1) अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए राज्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को राज्य सरकार द्वारा ऐसे पदों के सृजन के अध्वनीन अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, सभी विषयों में, जैसे कि सेवा निवृत्ति की आयु, वेतन भत्ते, लाभ और उपलब्धियों और अनुशासनात्मक विषयों में ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे जैसे कि राज्य सरकार के समतुल्य पदधारक कर्मचारियों की लागू हैं।

(3) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अन्य ऐसी सुविधाओं, भत्तों और लाभों जैसी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, के हकदार होंगे।

12. जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं.—(1) जिला प्राधिकरण के नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) जिला प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :

- (i) जिला मैजिस्ट्रेट ;
- (ii) पुलिस अधीक्षक ;
- (iii) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ;
- (iv) प्रधान, जिला बार एसोसिएशन ;
- (v) जिला न्यायवादी।

(3) राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस नियम के उप-नियम (4) में विहित अर्हता और अनुभव रखने वाले सदस्यों में से अन्य सदस्यों को दो वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकेगी और वे पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति जिला प्राधिकरण को सदस्य नामनिर्दिष्ट होने के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह :—

- (क) कोई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि समाज के कमजोर वर्गों, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी शामिल हैं, के उत्थान में संलिप्त हैं ;
- (ख) विधि या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति ; या
- (ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में हितवद्द हो।

(5) उप नियम (6) के अधीन इस नियम के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सभी सदस्य, जिला प्राधिकरण के कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे और समय-समय पर यथासंशोधित वित्त (विनियम) विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी०) बी० (7)-2/88, तारीख 24-5-1995 में अन्तर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला प्राधिकरण द्वारा संदत्त किए जाएंगे।

(6) यदि नामनिर्दिष्ट सदस्य सरकारी कर्मचारी है, तो वह उन दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते लेने का हकदार होगा; जिन पर वह, उसे लागू होने वाले सेवा नियमों के अधीन हकदार है और वह उन्हें जिला प्राधिकरण से न लेकर उस विभाग से लेगा, जिसमें वह कार्यरत है।

13. जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी.--(1) अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए, जिला प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा ऐसे पदों के सृजन के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने की शक्ति होगी।

(2) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी सभी विषयों में जैसे कि सेवा निवृत्ति की आयु, वेतन, भत्ते, लाभ और उपलब्धियाँ और अनुशासनात्मक विषयों में, ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे जैसे कि राज्य सरकार के समस्त पदधारक कर्मचारियों को लागू हैं।

(3) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अन्य ऐसी सुविधाओं, भत्तों और लाभों, जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएँ, के हकदार होंगे।

14. ताल्लुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों का अनुभव और अर्हताएं.--(1) ताल्लुक विधिक सेवा समिति के 6 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) ताल्लुक विधिक सेवा समिति के पदेन सदस्य निम्नलिखित होंगे:--

- (i) उपमण्डलाधिकारी (सिविल);
- (ii) उपमण्डल पुलिस अधिकारी;
- (iii) प्रधान, ताल्लुक बार एसोसिएशन;

(3) राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस नियम के उपनियम (4) में विहित अर्हता और अनुभव रखने वाले सदस्यों में से अन्य सदस्यों को दो वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकेगी और वे पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति ताल्लुक विधिक सेवा समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट होने के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि--

(क) कोई सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि समाज के कमजोर वर्गों जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी हैं, के उत्थान में संलग्न हैं; या

(ख) विधि या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति; या

(ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध हो।

(5) उप नियम (6) के अधीन, इस नियम के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सभी सदस्य, ताल्लुक, विधिक सेवा समिति के कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते के संदाय के हकदार होंगे और समय-समय पर यथासंशोधित वित्त (विनियम) विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या: फिन 0 (सी 0) बी 0 (7)-2/88, तारीख 24-5-1995 में अन्तर्विष्ट हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के अनुसार ताल्लुक समिति द्वारा संदत्त किए जाएंगे।

(6) यदि नामनिर्दिष्ट सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो उन दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा, जिन पर वह उस लागू होने वाले सेवा नियमों के अधीन, हकदार है और वह उन्हें ताल्लुक विधिक सेवा समिति से न लेकर उस विभाग से लेगा जिसमें वह कार्यरत है।

15. जिला/ताल्लुक विधिक सेवा समिति (समितियाँ) के सदस्यों का हटाया जाना:—जिला/ताल्लुक विधिक सेवा समिति का नामनिर्दिष्ट सदस्य, राज्य सरकार द्वारा, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित उन्हीं परिस्थितियों और शर्तों के अधीन हटाया जा सकेगा जैसे कि नियम 5 के उपनियम (2), (3), (4) और (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की दशा में लागू है।

16. ताल्लुक विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी:—(1) अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए ताल्लुक विधिक सेवा समिति को राज्य सरकार द्वारा ऐसे पदों के सृजन के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(2) ताल्लुक विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी सेवा निवृत्ति की आयु, वेतन और भत्ते, लाभ और उपलब्धियों और अनुशासनात्मक विषयों में ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे जैसे कि राज्य सरकार के समतुल्य पदधारक कर्मचारियों को लागू हैं।

(3) ताल्लुक विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और लाभों के जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं के हकदार होंगे।

17. सर्वोच्च न्यायालय से अन्यथा न्यायालयों में विधिक सेवाओं के लिए पात्रता:—भारत का कोई भी नागरिक, जिसकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपये से अधिक नहीं है, अधिनियम की धारा, 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए हकदार होगा।

18. कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों से अन्यथा व्यक्तियों का लोक अदालतों की पीठ में नियुक्ति हेतु अनुभव और अर्हताएं:—कोई भी व्यक्ति लोक अदालत की पीठ में सम्मिलित किए जाने के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह:—

(क) कोई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, जो समाज के कमजोर वर्गों, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ, महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी हैं, के उत्थान में संलिप्त हैं; या

(ख) कोई स्थाई अधिवक्ता या अध्यापक; या

(ग) कोई विख्यात व्यक्ति जो विधिक सेवा स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध हो।

19. विधिक सहायता बोर्ड की आस्तियों का अन्तरण:—(1) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन पर:—

(i) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सहायता का विघटन हो जाएगा;

- (ii) उक्त बोर्ड से सम्बन्धित सभी स्थावर और जंगम सम्पत्ति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में निहित होगी और इसे प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा अधिनियम, 1987 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उद्देश्यों और प्रयोजन के लिए उपयोजित किया जाएगा;
- (iii) बोर्ड के सभी कृण और दायित्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अन्तरित हो जाएंगे और तत्पश्चात इसके द्वारा पूर्वोक्त सम्पत्ति से उन्मोचित और चुकाए जाएंगे।

(2) उच्च न्यायालय, जिला और ताल्लुक स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों/समितियों के गठन पर निरसित नियमों के अधीन गठित विधिक सेवा समितियों की सभी सम्पत्तियाँ और आस्तियाँ इन नियमों के अधीन गठित तत्स्थानी विधिक सेवा प्राधिकरणों/समितियों को अन्तरित, और, में निहित हो जाएंगी।

20. अस्थायी उपबन्ध—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश राज्य गरीबों को कानूनी सहायता नियम, 1980 के अधीन गठित और हिमाचल प्रदेश विधिक सहायता नियम, 1984 के नियम 21 के अधीन गठित सन्ने गए विद्यमान विधिक सहायता बोर्ड और समितियाँ तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्च न्यायालय सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और ताल्लुक विधिक सेवा समितियों का इन नियमों के अधीन गठन नहीं कर दिया जाता।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व नियम-22 के उप नियम (1) के अधीन निरस्त नियमों द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों और प्राधिकार के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा बोर्ड या किन्हीं विधिक समितियों में से किसी के भी द्वारा की गई कोई बात या कार्रवाई, (जिसके अन्तर्गत स्वीकृत आवेदन या दी गई सहायता भी है) विधि मान्य रूप से की गई समझी जाएगी, मानों कि इन नियमों के उपबन्ध सभी महत्वपूर्ण समयों पर प्रवृत्त थे और तदनुसार उक्त हिमाचल प्रदेश विधिक सहायता बोर्ड या विधिक सहायता समितियों में से किसी एक द्वारा की गई बात या कार्रवाई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या यथास्थिति, तत्स्थानी विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति द्वारा की गई समझी जाएगी।

21. सेवाओं का अन्तरण.—इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व उक्त बोर्ड/समिति में कार्यरत राज्य विधिक सहायता बोर्ड की दशा में राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण का और राज्य सहायता समिति की दशा में तत्स्थानी विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति का अधिकारी या कर्मचारी बन जाएगा और उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं सेवा शर्तों और निबन्धनों पर और उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पदधारण करेगा जो उसे पूर्वतर प्राप्त थे और जबकि उनका नियोजन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में, या यथास्थिति, तत्स्थानी विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति में समाप्त नहीं कर दिया जाता, और जब तक उसके पारिश्रमिक, निबन्धन और शर्तों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता, इस पर बना रहेगा और राज्य विधिक सहायता बोर्ड/विधिक सहायता समिति के अधीन की गई सेवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या यथास्थिति, तत्स्थानी विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति के अधीन सेवा समझी जाएगी।

22. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) नियम 20 और 21 के उद्देश्यों के अधीन रहते हुए हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा नियम, 1984 को एतद्वारा निरसित लिया जाता है।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, की गई कोई बात या कार्रवाई या निरसित नियमों के अधीन जारी कोई प्रादेश या अनुदेश इन नियमों के अधीन की गई या जारी समझी जाएगी मानो कि यह नियम उस दिन को प्रवृत्त थे जिसको ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी या ऐसे प्रादेश या अनुदेश जारी किए गए थे।

प्रादेश द्वारा,

के 0 सी 0 सूद,
सचिव (विधि)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. LLR-A(3)-1/95, dated 31-10-1995, as required under clause (3) of Article 313 of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 31st October, 1995

No. LLR-A (3) 1/95.—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1995.

(2) These shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires.—

- (a) “Act” means the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987) ;
- (b) “Chief Justice” means the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh;
- (c) “Chairman” means the Executive Chairman of the State Authority, or, as the case may be, the Chairman of the High Court Legal Services Committee, or, as the case may be, the Chairman of the District Authority, or, as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committee;
- (d) “District Authority” means the District Legal Services Authority constituted under Section 9 of the Act;
- (e) “High Court Legal Services Committee” means a High Court Legal Services Committee constituted under Section 8-A of the Act;
- (f) “Secretary” means the Member-Secretary of the State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act, or, as the case may be, the Secretary of the High Court Legal Services Committee constituted under Section 8-A of the Act, or, as the case may be, the Secretary of the District Legal Services Authority constituted under Section 9 of the Act;
- (g) “State Authority” means the State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act;
- (h) “Taluk Legal Services Committee” means a Taluk Legal Services Committee constituted under Section 11-A of the Act;
- (i) “Taluk” means a Sub-Division in a District;
- (j) all other words and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. *Number, experience and qualifications of members of the State Authority.*—(1) The State Authority shall, including its Patron-in-Chief and the Executive Chairman, have not more than fifteen members.

(2) The following shall be *ex-officio* members of the State Authority:—

- (i) the Advocate General of the State;
- (ii) the Secretary in Department of Finance;
- (iii) the Secretary in the Department of Law;
- (iv) the Chairman of the Bar Council of Himachal Pradesh;
- (v) the Director General of Police of the State;
- (vi) the Secretary in the Welfare Department;
- (vii) two Chairmen of the District Authority, as may be nominated by the State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court.

(3) The State Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of the High Court, other members from amongst those possessing the experience and qualifications prescribed in sub-rule (4) of this rule.

(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the State Authority, unless he is—

- (a) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, rural and urban labour; or
- (b) an eminent person in the field of law or education; or
- (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

4. *Powers and functions of the Member-Secretary of the State Authority.*—The powers and functions of the Member-Secretary of the State Authority, *inter-alia*, shall be—

- (a) to give free legal services to the eligible and weaker sections;
- (b) to work out modalities of the Legal Services Schemes and programmes approved by the State Authority and ensure their effective monitoring and implementation;
- (c) to exercise the powers in respect of administrative; House keeping, Finance and budget matters as Head of the Department in the State Government;
- (d) to manage the properties, records and funds of the State Authority;
- (e) to maintain true and proper accounts of the State Authority including checking and auditing in respect thereof periodically;
- (f) to prepare annual income and expenditure account and balance-sheet of the said authority;
- (g) to liaise with the Social Action Groups and District and Taluk Legal Services Authorities;
- (h) to maintain, up-to-date and complete statistical information including progress made in the implementation of various Legal Services Programmes from time to time.

- (i) to process proposals for financial assistance and issue Utilization Certificates thereof;
- (j) to organise various Legal Services Programmes as approved by the State Authority and convene Meetings/Seminars and workshops connected with Legal Services Programmes and preparation of Reports and follow up action thereon;
- (k) to produce video/documentary films, publicity material, literature and publication to inform general public about the various aspects of the Legal Services Programmes;
- (l) to lay stress on the resolution of Rural Disputes and to take extra measures to draw schemes for effective and meaningful Legal Services for settling Rural Disputes at the door steps of the rural people.
- (m) to perform such of the functions as are assigned to him under the schemes formulated under section 4 (b) of the Act; and
- (n) to perform such other functions as may be expedient for efficient functioning of the State Authority.

5. *Terms of office and other conditions of appointment of Members and Member-Secretary of the State Authority.*—(1) The term of office of the members of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 by the State Government shall be two years and shall be eligible for renomination.

(2) A member of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 may be removed by the State Government, in consultation with the Chief Justice, if—

- (a) he fails, without sufficient cause, to attend three consecutive meetings of the State Authority or five meetings held within the space of two years; or
- (b) has been adjudged as insolvent; or
- (c) has been convicted of an offence, which in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or
- (d) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in the State Authority prejudicial to the public interest.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), no member shall be removed from the State Authority on the ground specified in clause (d) of that sub-rule unless the Chief Justice, on a reference being made to him in this behalf by the State Government has, on an enquiry held by him in accordance with such procedure as he may specify in this behalf, recommended that the member ought, on such grounds, to be removed.

(4) A member may, by writing under his hand, addressed to the Chairman, resign from the State Authority and such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the State Government in consultation with the Chief Justice, or on the expiry of 30 days from the date of tendering resignation, whichever is earlier.

(5) If any member nominated under sub-rule (3) of rule 3 ceases to be member of the State Authority for any reason, the vacancy shall be filled up in the same manner as the original nomination and the person so nominated shall continue to be a member for the remaining term of the member in whose place he is nominated.

(6) Subject to the provisions of sub-rule (7), all members nominated under sub-rule (3) of rule 3 shall be entitled to payment of travelling allowance and daily allowance in respect

of journeys performed in connection with the work of the State Authority and shall be paid by the State Authority in accordance with the Himachal Pradesh Government instructions contained in Finance Regulation Department Office Memorandum No. Fin-(c)-B (7)-2/88, dated 24-5-1995, as amended from time to time.

(7) If the nominated member is a Government employee, he shall be entitled to draw the travelling allowance and daily allowance at the rates to which he is entitled to under the service rules applicable to him and shall draw from the department, in which he is employed and not from the State Authority.

(8) The member-Secretary of the State Authority shall be the whole time employee and shall hold office for a term not exceeding five years.

(9) In all matters like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements, and disciplinary matters, the Member-Secretary shall be governed by the rules, as are applicable to the members of the State Higher Judicial Services and he shall be on deputation to the State Authority.

6. *Officers and other employees of the State Authority.*—The State Authority shall have the power to make the appointments of the officers and other employees of the Authority, for the efficient performance of its functions under the Act, subject to the creation of such posts by the State Government.

7. *Special provisions for Patron-in-chief, the Executive Chairman and Chairman High Court Legal Services Committee.*—(1) The Patron-in-Chief, the Executive Chairman and the Chairman High Court Legal Services Committee being a sitting Judge of the High Court shall be entitled to payment of travelling allowance and daily allowance in respect of journeys performed in connection with the work of the State Authority and paid by the State Authority in accordance with the provisions of the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, as amended from time to time.

(2) The Executive Chairman of the State Authority, in case he is a retired Judge of the High Court, shall be provided with a staff car and a staff car driver by the State Authority and the expenditure on account of pay and allowance of the staff car driver as well as maintenance and repairs of the cars shall be borne by the said Authority.

8. *Conditions of Service of Executive Chairman in a case of retired Judge.*—Where the Executive Chairman is a retired judge of the High Court—

- (i) his terms and conditions of service shall be such as are specified in Government of India, Ministry of Finance Department of Expenditure O.M. No. 19048/7/80-E, IV, dated the 8th October, 1987 or such other relevant order of the State Government as may be applicable to the retired Judges of the High Court appointed on commissions/committees.
- (ii) he shall be entitled to sumptuary allowance @ of rupees 500/- per month to be paid by the State Authority.
- (iii) he shall be permitted to subscribe to the Contributory Provident Fund of the State.

9. *Conditions of service and salary and allowances of officers and other employees of the State Authority.*—(1) The officers and other employees of the State Authority shall in all matters, like age of retirement, pay allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters, be governed by such rules, as are applicable to the employees of the State Government holding equivalent posts.

(2) The officers and other employees of the State Authority shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time.

10. *Experience and qualifications of the Secretary of the High Court Legal Services Committee.*—A person shall not be qualified for appointment as Secretary of the High Court Legal Services Committee unless he is an officer of the High Court not below the rank of Additional Registrar of the High Court.

11. *Conditions of service and salary and allowances of officers and other employees of the High Court Legal Services Committee.*—(1) The High Court Legal Services Committee shall have the power to make appointments of officers and employees of the Committee for the efficient performance of its functions under the Act subject to the creation of such posts by the State Government.

(2) The officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall in all matters, like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters, be governed by such rules, as are applicable to the employees of the State Government holding equivalent post.

(3) The officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time.

12. *Number, experience and qualifications of members of the District Authority.*—

(1) The District Authority shall have not more than nine members.

(2) The following shall be *ex-officio* members of the District Authority;—

- (i) District Magistrate;
- (ii) Superintendent of Police;
- (iii) Chief Judicial Magistrate;
- (iv) President, District Bar Association; and
- (v) District Attorney.

(3) The State Government may nominate, in consultation with Chief Justice of the High Court, other members from amongst those possessing the qualifications and experience prescribed in sub-rule (4) of this rule, for a period of two years and they shall be eligible for renomination.

(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the District Authority unless he is:—

- (a) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children and rural labour;
- (b) an eminent person in the field of law or education; or
- (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes;

(5) Subject to sub-rule (6) all members nominated under sub-rule (3) of this rule shall be entitled to payment of travelling allowance and daily allowance in respect of journeys performed in connection with the work of the District Authority and shall be paid by the District

Authority in accordance with the Himachal Pradesh Government instructions contained in the Finance (Reg.) Department Office Memo No. Fin (C)-B (7)-2/88, dated 24-5-1995, as amended from time to time.

(6) If the nominated member is a Government employee, he shall be entitled to draw travelling allowance and daily allowance at the rates to which he is entitled to under the service rules applicable to him and shall draw it from the department in which he is employed and not from the District Authority.

13. Officers and other employees of the District Authority.—(1) The District Authority shall have the power to make appointment of officers and other employees for the efficient performance of its functions under the Act, subject to the creation of such posts by the State Government.

(2) The officers and other employees of the District Authority shall in all matters like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters, be governed by such rules, as are applicable to the employees of the State Government holding equivalent posts.

(3) The officers and other employees of the District Authority shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time.

14. Experience and qualifications of members of the Taluk Legal Services Committee.—

(1) The Taluk Legal Services Committee have not more than six members.

(2) The following shall be *ex-officio* members of the Taluk Legal Services Committee :—

(i) Sub Divisional Officer (Civil) ;

(ii) Sub Divisional Police officer ;

(iii) President, Taluk Bar Association.

(3) The State Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of the High Court, other members from amongst those possessing the qualifications and experience prescribed in sub-rule (4) of this rule, for a period of two years and they shall be eligible for re-nomination.

(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the Taluk Legal Services Committee unless he is—

(a) an eminent Social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children and rural labour; or

(b) an eminent person in the field of law or education; or

(c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

(5) Subject to sub-rule (6), all members nominated under sub-rule (3) of this rule shall be entitled to payment of travelling allowance and daily allowance in respect of journeys performed in connection with the work of Taluk Legal Services Committee and shall be paid

by the Taluk Committee in accordance with the Himachal Pradesh Government instructions contained in the Finance (Regulation) Department Office Memorandum No. Fin(C)-B(7)-2/88, dated 24-5-1995, as amended from time to time.

(6) If the nominated member is a Government employee, he shall be entitled to draw travelling allowance and daily allowance at the rates to which he is entitled under the service rules applicable to him and shall draw it from the department in which he is employed and not from the Taluk Committee.

15. *Removal of members of District/Taluk Legal Services Committee(s).*—A nominated member of the District/Taluk Legal Services Committee may be removed by the State Government in consultation with the Chief Justice under the same circumstances and conditions, *mutatis mutandis*, as are applicable in the case of a member of the State Authority under sub-rules (2), (3), (4) and (5) of rule 5.

16. *Officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee.*—(1) The Taluk Legal Services Committee shall have power to make appointments of officers and other employees for the efficient performance of its functions under the Act, subject to the creation of such posts by the State Government.

(2) The officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee shall in all matters like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters, be governed by such rules, as are applicable to the employees of the State Government holding equivalent posts.

(3) The officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time.

17. *Eligibility for Legal Services in Courts other than Supreme Court.*—Any citizen of India whose annual income from all sources does not exceed Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen thousand) shall be entitled to legal services under clause (h) of section 12 of the Act.

18. *Experience and qualifications of persons other than serving or retired Judicial Officer on Bench of the Lok Adalats.*—A person shall not be qualified to be included in the Bench of Lok Adalat, unless he is—

- (a) an eminent social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people; including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, rural and urban labour; or
- (b) a lawyer of standing or teacher; or
- (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes and Programmes.

19. *Transfer of assets of Legal Aid Board.*—(1) Upon the constitution of the State Legal Services Authority:—

- (i) the Himachal Pradesh State Legal Aid Board shall stand dissolved;
- (ii) all property, movable, or immovable, belonging to the said Board shall vest in the State Legal Services Authority and shall be applied by the authority to the objects and purposes of the Legal Services Act, 1987 and the rules framed thereunder;
- (iii) All the debts and liabilities of the Board shall be transferred to the State Legal Services Authority and shall thereafter be discharged and satisfied by it out of the aforesaid property.

(2) Upon the constitution of Legal Services Authority/Committees at High Court, District and Taluk level, all properties and assets of the Legal Aid Committees constituted under the repealed rules shall stand transferred and vested in the corresponding Legal Services Authorities/Committees constituted under these rules.

20. Transitory Provisions.—(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the existing Legal Aid Board and committees constituted under the Himachal Pradesh State Legal Aid to the Poor Rules, 1980 and deemed to be continued under rule 21 of the Himachal Pradesh Legal Aid Rules, 1984 shall continue to function till the State Legal Services Authority, the High Court Legal Services Committee, the District Legal Services Authorities and the Taluk Legal Services Committees are constituted under these rules.

(2) Anything done or any action taken (including applications admitted or legal aid granted) by the Himachal Pradesh State Legal Aid Board or any of the Legal Aid Committees, immediately before the commencement of these rules in the exercise or purported exercise of its powers and authority conferred by or under the rules repealed under sub-rule (1) of rule 22 shall be deemed to have been validly done or taken as if the provisions of these rules, had been in force at all material times and, accordingly, anything done or any action taken by the said Himachal Pradesh Legal Aid Board or any of the Legal Aid Committees shall be deemed to have been done or taken by the State Legal Services Authority, or as the case may be, by the corresponding Legal Services Authority/Committee.

21. Transfer of Services.—Every officer or other employee of the Himachal Pradesh State Legal Aid Board or its Committee, in the employment of the said Board/Committee, immediately before the commencement of the rules, shall on and from the date on which these rules come in to force, become the officer or other employee of the State Legal Services Authority, in the case of State Legal Aid Board, and of the corresponding Legal Services Authority/Committee in the case of Legal Aid Committees; and shall hold his office or service therein for the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as he would have held the same and shall continue to do so unless and until his employment in the State Legal Services Authority or, as the case may be, in the corresponding Legal Services Authority/Committee is terminated and until his remuneration, terms and conditions are duly altered by the State Legal Services Authority, and the service rendered under the State Legal Aid Board/Legal Aid Committee shall be deemed to be the service rendered under the State Legal Services Authority or as the case may be, under the corresponding Legal Services Authority/Committees.

22. Repeal and Savings.—(1) Subject to the provisions of rules 20 and 21, the Himachal Pradesh Legal Aid Rules, 1984 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), anything done, or any action taken or orders or directions issued under the repealed rules, shall be deemed to have been done or taken or issued under these rules as if these rules were in force on the day on which such thing was done or action was taken or such order or direction was issued.

By order,

K. C. SOOD,
Secretary (Law).

